



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

**EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2005/चैत्र 1, 1927

No. 35]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2005/CHAITRA 1, 1927

## महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 17 मार्च, 2005

सं. टीएएमपी/4/2004-सामान्य.—महापत्रन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 की 38) की धारा III के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी नीति निदेशों के अनुपालन में और कथित अधिनियम की धाराओं 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण, तटीय व्यापार हेतु कार्गो संबंधी रियायती प्रभारों में से लौह अयस्क और लौह अयस्क गिट्रियों को बाहर रखने के लिए, संलग्न आदेशानुसार अपने पिछले आदेश सं. टीएएमपी/4/2004- सामा., दिनांक 7 जनवरी, 2005 में एतद्वारा आंशिक संशोधन करता है।

## महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/4/2005-सामान्य

आदेश

(मार्च, 2005 के 15वें दिन पारित)

तटीय कार्गो/कन्टेनरों/पोतों से संबंधित प्रभारों के लिए रियायती दरें निर्धारित करने हेतु सामान्य सशर्तताओं का एक समुच्चय शामिल करते हुए सभी महापत्रन न्यासों और प्राइवेट टर्मिनल आपैरेटरों के द्वारा में संशोधन करने के लिए भारत सरकार द्वारा महापत्रन न्यास अधिनियम धारा III के अन्तर्गत जारी नीति निदेशों के अनुपालन में 7 जनवरी, 2005 को इस प्राधिकरण ने एक आदेश पारित किया था। यह आदेश राजपत्र सं. 3 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में 12 जनवरी, 2005 को अधिसूचित किया गया था।

(2) जहाँ तक तटीय कार्गो/कन्टेनरों के कार्गो/कन्टेनरों संबंधी प्रभारों में रियायतों का संबंध है, आरम्भ की गई सामान्य सशर्तताओं में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित निर्धारण भी किया गया था;

2.1 कच्चे तेल सहित तापीय कोयले तथा पीओएल के अतिरिक्त सभी तटीय कार्गो/कन्टेनरों के लिए कार्गो/कन्टेनरों संबंधी प्रभार कार्गो/कन्टेनरों संबंधी सामान्य प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होने चाहिए।

(3) नौवहन, सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने विशाखापत्तनम् पत्रन न्यास द्वारा प्रस्तुत एक अध्यावेदन पर विचार किया और तटीय व्यापार के लिए रियायती प्रभारों हेतु निदेशों से लौह अयस्क और लौह अयस्क गिट्रियों को छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, नौव. सड़क परि. और रा. मा. मंत्रालय ने अपने पत्र सं. पीआर-14019/29/2001-पी.जी., दिनांक 9 मार्च के द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2005 के अपने पिछले आदेश के क्रियान्वयन से लौह अयस्क और लौह गिट्रियों को तुरंत प्रभाव से छूट प्रदान करने हेतु इस प्राधिकरण के लिए महापत्रन न्यास अधिनियम की धारा III के अन्तर्गत एक अन्य नीति निदेश जारी किया है।

(4) तदनुसार, यह प्राधिकरण दिनांक 7 जनवरी, 2005 के अपने पिछले आदेश के पैरा 5 में प्रदत्त सामान्य सशर्तता सं. 2.1 में निम्नानुसार संशोधन करता है :

2.1. "लौह अयस्क और लौह अयस्क गिट्रियों के कच्चे तेल समेत तापीय कोयले और पीओएल के अतिरिक्त सभी तटीय कार्बो/कन्टेनर हेतु कोर्टो/कन्टेनर संबंधी प्रभार, सामान्य कार्बो/कन्टेनर संबंधी तदनुरूप प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होने चाहिए।"

(5) सभी महापरतन व्यासों और प्राइवेट टर्मिनलों को अपने दरमान तदनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है।

(6) संशोधित प्रावधान, इसके भारत का राजपत्र को अधिसूचित होने पर तुरंत प्रभावी हो जाएगा।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/2004/असाधा.]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 17th March, 2005

**No. TAMP/4/2004-GenL**—In compliance of a policy direction issued by the Government of India under Section III of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the said Act, the Tariff Authority for Major Ports hereby partially amends its earlier Order No. TAMP/4/2004-GenL, dated 7 January, 2005 to exclude iron ore and iron ore pellets from the concessional cargo related charges for coastal trade, as in the Order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/4/2004-GenL

### ORDER

(Passed on this 15th day of March, 2005)

In compliance of a policy direction issued by the Government of India under section III of the Major Port Trusts Act to prescribe concessional rates for coastal cargo/containers/vessels related charges, this Authority passed an Order on 7 January, 2005 to amend the Scale of Rates of all the major port trusts and private terminal operators by inserting a set of general conditionalities. This Order was notified in the Gazette of India on 12 January, 2005 under Gazette No. 3.

(2) Insofar as the concessions in cargo/container related charges to coastal cargo/containers are concerned, the following prescription, *inter alia*, was made in the general conditionalities introduced :

"2.1. The cargo/container related charges for all coastal cargo/containers, other than thermal coal and POL including crude oil, should not exceed 60% of the normal cargo/container related charges."

(3) The Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (MSRT&H) has considered a representation in made by Visakhapatnam Port Trust and decided to exempt iron ore and iron ore pellets from the directions for concessional charges for coastal trade. The MSRT&H has accordingly, *vide* its letter No. PR-14019/29/2001-PG dated 09 March, issued another policy direction under section III of the MPT Act to this Authority to exempt iron ore and iron ore pellets from the operation of its earlier order of 7 January, 2005 with immediate effect.

(4) This Authority accordingly amends the general conditionality No. 2.1 prescribed in para 5 of its earlier Order dated 7 January, 2005 as follows :

"2.1. The cargo/container related charges for all coastal cargo/containers, other than thermal coal, POL including crude oil, iron ore and iron ore pellets, should not exceed 60% of the corresponding charges for normal cargo/container related charges."

(5) All the major port trusts and private terminals are directed to amend their Scale of Rates accordingly.

(6) The amended provision shall come into effect immediately on its notification in the Gazette of India.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT/III/IV/143/2004/Exty.]